

तिब्बत देश



तिब्बत पर चीन के कब्जे के पीछे चेयरमैन माओ की दूरदृष्टि के सबूत आए दिन सामने आते रहते हैं। पहले तिब्बत के रास्ते चीन ने दक्षिण एशिया के साथ अपनी सीमाएं मिलाकर एशिया पर अपने दबदबे का आधार तैयार किया। बाद में तिब्बत को फौजी ठिकाने में बदलकर अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार किया। उसके बाद वहां चीनी नागरिकों को बसाकर और वहां के खनिजों के दोहन का अभियान शुरू करके चीन के औपनिवेशिक हितों की नई नींव डाली। और अब तिब्बत के विशाल जल खजाने को अपने हितों के लिए लूटने का नया अभियान चलाकर विश्वशक्ति बनने के खाब को असली रूप देने में लग गया है।

चीन से आने वाले समाचारों ने ब्रह्मपुत्र पर उस चीनी डैम के निर्माण कार्य की अंतिम तौर पर पुष्टि कर दी है जिसे चीन सरकार अभी तक एक 'कपोल कल्पित' अफवाह और एक 'गैर जरूरी, असंभव और अवैज्ञानिक' परियोजना बताकर इस योजना के अस्तित्व को ही नकारती आ रही थी। भारत की पूर्वी सीमा के निकट तिब्बत के नामचा बारवा में लगभग 130 करोड़ डालर (5850 करोड़ रु) के खर्च पर बनाया जा रहा यह झाम्गू डैम दुनिया की सबसे बड़ी चीनी पनबिजली योजना का पहला चरण है।

चीन सरकार के विभिन्न विभागों और कंपनियों द्वारा प्रकाशित जानकारी के अनुसार 2020 तक पूरी होने वाली यह परियोजना दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी आश्चर्य माने जाने वाली चीनी परियोजना 'श्री गार्जिस डैम' की बिजली क्षमता (18 हजार मेगावाट) से भी दुगुनी बड़ी (38 हजार मेवा) परियोजना होगी। और इसमें श्री गार्जिस जैसे दो या तीन डैम होंगे।

पहले चरण में लगभग 2300 मीटर की ऊंचाई से पानी की गिरावट के दोहन के लिए 16 किमी लंबी भूमिगत सुरंगों का काम लगभग पूरा हो चुका है। यहां पैदा होने वाली 510 मेगावाट की पहली बिजली इकाई का उपयोग नए डैम और विशालकाय अंडरग्राउंड सुरंगें बनाने के लिए किया जाएगा। चीन का अंतिम इरादा ब्रह्मपुत्र के पानी को पंपिंग करके उत्तरी चीन में मृतप्राय हो चुकी यैलो रिवर को जिंदा करना तथा शिंजियांग के गोबी रेगिस्तान तक पहुंचाना है।

इसका सामरिक पहलू यह है कि परियोजना के पूरा होने पर चीन सरकार और उसकी सेना ब्रह्मपुत्र के पानी को किसी भी समय भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करके भारत के असम और बंगलादेश में बाढ़ या सूखे की हालत पैदा कर सकेगी और इस इलाके में भारतीय सुरक्षा सेनाओं की आवाजाही को नियंत्रित कर सकेगी।

ब्रह्मपुत्र पर यह चीनी परियोजना चीन के उस अभियान का पहला चरण है जो उसने 1951 में जबरन कब्जाए गए तिब्बत के पानी के विशाल भंडारों पर चीनी नियंत्रण के लिए शुरू किया है। तिब्बत में विशाल बर्फ के भंडार के कारण उसे धरती का 'तीसरा ध्रुव' भी माना जाता है। यहां से निकलने वाली नदियों का 90 प्रतिशत पानी चीन, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जैसे कई देशों के तीन अरब लोगों के लिए जीवनरेखा है और पूरे एशिया के पर्यावरण को प्रभावित करता है।

प्राकृतिक पानी पर इस तरह के कब्जे वाली यह परियोजना नदियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय नियमों और परंपरा का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है। पर्यावरण की दृष्टि से भी दुनिया भर के विशेषज्ञ चीन की इस परियोजना को तिब्बत, भारत और बंगलादेश के अलावा पूरे एशिया के लिए खतरनाक बता चुके हैं। लेकिन पर्यावरण के लिए 'श्री गार्जिस डैम' और तिब्बत में चीनी रेलवे जैसी खतरनाक योजनाओं को दुनिया भर के विरोध के बावजूद पूरा करने वाली चीन सरकार इस मामले में भी अपनी दादागिरी पर कायम है।

तिब्बत के पानी की चीनी लूट और ब्रह्मपुत्र

इस चीनी परियोजना से परदा हटने पर चीन सरकार भारत और बांग्लादेश को दिलासा दे रही है यह नदी के पानी को रोककर इस्तेमाल करके वापस छोड़ देने वाली मात्र एक 'रन ऑफ द रिवर' परियोजना है। पर दूसरी ओर वह यह दलील भी दे रही है कि इन दोनों देशों को चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि भारत में प्रवेश के बाद ब्रह्मपुत्र को भारतीय पहाड़ों से काफी पानी मिल जाता है।

दुर्भाग्य से भारत सरकार की ओर से इस बारे में जो प्रतिक्रिया आयी है वह चीन के आगे रिरियाने की उसी परंपरागत शैली का प्रदर्शन है जो 1962 के चीनी हमले में हुए राष्ट्रीय अपमान के बाद भारतीय शासकों और नीति निर्धारकों के व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। इस समाचार पर टिप्पणी करते हुए भारतीय विदेशमंत्री श्री एस एम कृष्णा ने देश को तसल्ली देते हुए कहा है कि "इस पर तुरंत हाय-तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। जिन तथ्यों पर ये समाचार आधारित हैं, हमें पहले से ही उनका पता था।" इस मामले में चीन द्वारा पेश किए गए बचाव को लगभग भारतीय दलील की तरह पेश करने के दबू अंदाज़ में उन्होंने यहां तक कह डाला कि "हमने अपने सूत्रों से पता लगाया है कि चीन की यह एक 'रन ऑफ द रिवर' परियोजना है जिसका भारत में ब्रह्मपुत्र के बहाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा।" भारतीय हितों के समर्थन में बोलने के बजाए चीन के आगे घुटने टेकने की अपनी शैली दिखाते हुए उन्होंने यह भी कह डाला कि असली जरूरत तो यह है कि भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारें ब्रह्मपुत्र में उपलब्ध पानी का सही इस्तेमाल करना सीखें।

भारत की सीमा से ठीक पहले एक विशाल चीनी डैम को महज एक 'रन ऑफ द रिवर' निर्माण बताने वाले भारतीय विदेश मंत्री से यह अपेक्षा तो की जा सकती थी कि उन्हें कम से कम दस साल पुराना इतिहास ही याद रहता। लगता है वह हिमाचल के उस पार तिब्बत में पारी चू नदी की वह घटना भूल चुके हैं जब कुछ साल पहले भू-स्खलन से बनी कृत्रिम झील को चीन सरकार ने बारूद से उड़ाकर अभूतपूर्व बाढ़ पैदा कर दी थी जिसने भारतीय क्षेत्र में भयंकर तबाही मचायी थी। झाम्गू परियोजना चीन के हाथ में भारत के खिलाफ इससे भी भयंकर स्थायी हथियार दे देगी।

आर्थिक विकास के नाम पर चीन की विवेकहीन नीतियों के कारण तिब्बत के 46 हजार ग्लेशियरों पर पहले से ही नया संकट खड़ा हो चुका है। पिछले 40 साल में उनमें से 20 प्रतिशत हिमनद पीछे सरक चुके हैं। चीन की औद्योगिक और दूसरी नीतियों के कारण हुआंग हो (यैलो रिवर) समेत कई नदियां लगभग मर चुकी हैं। आधुनिकीकरण की इस अंधी दौड़ में चीन 25 हजार से ज्यादा विशाल डैम बनाकर पर्यावरण को पहले ही भारी नुकसान पहुंचा चुका है। तिब्बत, निकटवर्ती हिमालय क्षेत्रों, तिएन शान और अल्ताई से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, सालवीन, मेकांग, यांग्त्सी, हुआंग हो, इरतिश, आमू दरिया, सिर दरिया, इली, सिंधु और गंगा जैसी नदियों पर चीन और तिब्बत में हो रहे पर्यावरण परिवर्तन का बुरा असर पड़ना कभी से जारी है।

असल में भारतीय विदेशमंत्री को ब्रह्मपुत्र पर चीन की झाम्गू परियोजना के मामले में चीन का तुष्टिकरण करने के बजाए इस मौके का इस्तेमाल दुनिया को यह समझाने के लिए करना चाहिए था कि तिब्बत पर गैरकानूनी कब्जा जमाकर अब चीन ने वहां की नदियों के पानी की डकैती का नया अभियान शुरू किया है। ऐसा करके वह बंगलादेश, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जैसे उन देशों में भारत की साख को बढ़ाते और उनके अधिकारों के लिए आवाज़ भी उठाते जो चीनी दादागिरी से परेशान हैं और चीन द्वारा पानी की चोरी के कारण असहाय महसूस कर रहे हैं।

ब्रह्मपुत्र पर चीन के नए खेल ने भारत को एक बार फिर यह याद दिलाया है कि तिब्बत पर चीन के कब्जे की ओर आंखें मूंदकर भारत सरकार ने तिब्बत से कहीं ज्यादा भारतीय हितों को बलिदान किया है।

— विजय क्रान्ति

नाबा में हाल में हुई घटनाएँ

अभियान शुरू किया गया।

गतिरोध जारी रहा और सैकड़ों स्थानीय लोगों को मठ के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा ड्यूटी में लगाया गया। भिक्षुओं के तब तक मठ से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई जब तक सरकारी अधिकारी उनकी 'देशभक्ति पुनर्शिक्षा' अभियान को पूरा नहीं कर लेते।

16 मार्च, 2011

20 साल के फुंसोक जारुतसांग के आत्मदाह के प्रयास ने नाबा में भिक्षुओं और आम जनता के एक बड़े विरोध प्रदर्शन को चिनगारी दे दी। तीन साल पहले इसी दिन चीनी सुरक्षा बलों यहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले एक समूह पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी जिससे कम से कम 10 लोग मारे गए थे।

17 मार्च, 2011

- 1 नाबा में स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 3 बजे फुंसोक की मौत हो गई।
- 2 अपर मिडल स्कूल के विद्यार्थी भूख हड़ताल पर बैठ गए।

19 मार्च, 2011

नाबा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई।

20 मार्च, 2011

- 1 नाबा के अंदर और बाहर सभी जगहों पर सुरक्षा और सख्त की गई।
- 2 कीर्ति मठ के अधिकारियों और नाबा के अंदर और उसके आसपास के सामुदायिक नेताओं को निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि 20 मार्च, 2011 को कोई भी तिब्बती निर्वासित तिब्बतियों के चुनाव संपन्न होने की खुशी में पटाखे जलाने, लोबान सुलगाने या पवन अश्व वाले प्रार्थना ध्वज हवा में उड़ाने जैसी गतिविधियां नहीं होंगी।

21 मार्च, 2011

नाबा के कीर्ति मठ में देशभक्ति पुनर्शिक्षा

22 मार्च, 2011

फुंसोक के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के संदेह में चार तिब्बतियों को हिरासत में ले लिया गया। इनमें फुंसोक के 19 वर्षीय भाई एवं कीर्ति मठ के भिक्षु लोबसांग सेतेन, फुंसोक के मामा लोबसांग सोन्ड्रु, मेउरुमा टाउनशिप के डिवीजन 2 के मूल निवासी और कीर्ति मठ के एक भिक्षु सुन्डु सामड्रुप और 16 साल के लोबसांग जामयांग को गिरफ्तार कर लिया गया। जामयांग को नाबा काउंटी के अपर तवा स्थित उनके घर से रात के 12 से 1 बजे के बीच गिरफ्तार किया गया।

23 मार्च, 2011

- 1 चीनी अधिकारियों ने कीर्ति मठ के भिक्षुओं को आदेश दिया कि चीनी नियमों एवं कानूनों के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएं।
- 2 भिक्षुओं को तीन पुस्तिकाओं की प्रतियां दी गईं। ये तीन पुस्तिकाएं थीं, 1—चीन जनवादी गणतंत्र (पीआरसी) का संविधान, 2—चीन के ध्वज के सम्मान से संबंधित कानून, 3—सार्वजनिक विवादों पर मध्यस्थता से संबंधित पीआरसी के नियम।

24 मार्च, 2011

- 1 नाबा और उसके आसपास के इलाकों से कई तिब्बतियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कीर्ति मठ से 24 साल के भिक्षु लोबसांग छोमफेल को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने उन्हें कहां

रखा है। इसी प्रकार नाबा काउंटी के ही छा टाउनशिप में स्थित अपर छुकले के कीर्ति मठ से जुड़े तांत्रिक कॉलेज से 32 साल के लोबसांग गोंडुप को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके गिरफ्तारी की वजह नहीं पता चल पाई है।

- 2 स्थानीय अधिकारियों ने नाबा काउंटी के अपर तवा और गामपा गावों में जनसभा बुलाकर लोगों को निर्देश दिया कि कीर्ति मठ में सुरक्षा ड्यूटी के लिए हर दिन हाजिरी दें ताकि भिक्षुओं द्वारा आगे कोई विरोध प्रदर्शन न होने पाए। यह कहा गया कि जो लोग हाजिरी बजाने में चूक करेंगे उन्हें प्रति दिन के हिसाब से 30 युआन का जुर्माना देना होगा।

25 मार्च, 2011

इस दिन एक और गिरफ्तारी हुई। कीर्ति मठ के 27 साल के भिक्षु और बीजिंग के अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय के छात्र लोबसांग सेपक को करीब 6 बजे शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई और उन्हें कहां रखा गया है।

1 अप्रैल, 2011

- 1 सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ा। कीर्ति मठ के चारों ओर नाकाबंदी कर रहे दस्तों का साथ देने के लिए बड़ी संख्या में चीनी सशस्त्र सेना के जवान भेजे गए। सैनिक मठ के प्रांगड़ में घुस गए और उन्होंने भिक्षुओं की स्वतंत्र तौर से आवाजाही पर रोक लगा दी। इनमें एक 70 साल के बुजुर्ग भिक्षु भी थे। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि

यदि मठ का यह घेराव ऐसे ही जारी रहा तो भिक्षुओं को अपने दैनिक जरूरतों को भी हासिल कर पाना मुश्किल होगा।

- 2 कीर्ति मठ पर सुरक्षा बलों का दमन जारी। 27 साल के लोबसांग गेलेक को गिरफ्तार कर लिया गया जो शायद एक भिक्षु हैं। मेउ रुमा गांव के मूल निवासी गेलेक को क्योंकि गिरफ्तार किया गया, इसकी वजह नहीं पता चल पाई है।

11 अप्रैल, 2011

कीर्ति मठ में एक और गिरफ्तारी। 31 साल के लोबसांग धार्ग्याल को मठ से गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी भी गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई।

12 अप्रैल, 2011

मठ के अंदर किसी के जाने पर रोक लगाए जाने के बाद तिब्बतियों में यह आशंका बढ़ गई कि चीनी अधिकारी कीर्ति मठ पर कयामत बरपाने की योजना बना रहे हैं और 18 से 40 साल के सभी भिक्षुओं को स्थानीय जेलों में भेजने की तैयारी की जा रही है, जहां उन्हें जबर्दस्ती 'राजनीतिक शिक्षा' दी जाएगी। सशस्त्र पुलिस और सैनिक तिब्बतियों को पीटकर और उनके ऊपर कुत्ते छोड़कर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहे।

13 अप्रैल, 2011

गतरोध जारी रहा और सैकड़ों स्थानीय लोगों को मठ के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा ड्यूटी में लगाया गया। भिक्षुओं के तब तक मठ से बाहर जाने पर रोक लगा

नाबा
अपन
मिडल
स्कूल के
विद्यार्थियों
के
परिसर
छोड़ने
पर रोक
लगा दी
गई।
फुंसोक
के
आत्मदाह
के प्रति
सहानुभूति
दिखाते
हुए
छात्रों ने
17 मार्च
से ही
भूख
हड़ताल
शुरू कर
दिया।

करीब 200 लोगों ने सशस्त्र बलों और पुलिस द्वारा भिक्षुओं की गिरफ्तारी को रोकने का प्रयास किया। इनमें से ज्यादातर लोग 60 साल के ऊपर के थे। इन विरोध करने वाले लोगों को बुरी तरह पीटा गया और दो लोगों की जान चली गई।

दी गई जब तक सरकारी अधिकारी उनकी 'देशभक्ति पुनर्शिक्षा' अभियान को पूरा नहीं कर लेते।

14 अप्रैल, 2011

कीर्ति मठ के वरिष्ठ भिक्षुओं और बीजिंग के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया। भिक्षुओं ने मठों के स्कूलों को बंद करने पर गहरी चिंता जताई, लेकिन यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट के मंत्री इसका समुचित जवाब देने में विफल रहे।

15 अप्रैल, 2011

- 1 नाबा काउंटी में और खासकर कीर्ति मठ में किसी तरह के जमावड़े या विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने प्रतिबंध बढ़ा दिया।
- 2 कीर्ति मठ से कई और गिरफ्तारियां की गईं, लेकिन गिरफ्तार भिक्षुओं के नाम की पुष्टि नहीं हो पाई है।
- 3 कीर्ति मठ में शुरू किया गया 'देशभक्ति पुनर्शिक्षा' अभियान सरकारी कर्मचारी और स्कूली बच्चों के लिए अनिर्वाय कर दिया गया। पास के जोग्ये काउंटी के सरकारी कर्मचारियों को भी कीर्ति मठ में 'देशभक्ति पुनर्शिक्षा' सत्र में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया।

16 अप्रैल, 2011

गहन 'देशभक्ति पुनर्शिक्षा' अभियान जारी, सुरक्षा बलों ने भिक्षुओं को धमकी दी कि यदि वे उनके आदेश का पालन करने में विफल रहे तो मठ को बंद कर दिया जाएगा।

17 अप्रैल, 2011

- 1 कीर्ति मठ में चीन का 'देशभक्ति पुनर्शिक्षा' जारी।
- 2 नाबा अपन मिडल स्कूल के विद्यार्थियों के परिसर छोड़ने पर रोक लगा दी गई। फुंसोक के आत्मदाह के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए छात्रों ने 17 मार्च से ही भूख हड़ताल शुरू कर दिया।
- 3 मेउ रुमा, ऊपरी एवं निचले छुकले, रारु, नाक्तसंगमा और छसांग के खानाबदोश क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सेना के जवान तैनात कर दिए गए। खानाबदोश लोगों को रारु घर में इकट्ठा कर उनको एक आदेश पर दस्तखत करने का मजबूर किया गया। इस आदेश को न तो उनकी भाषा में अनुवाद कर बताया गया और न ही इसके बारे में उन्हें कोई समझाने वाला था।

18 अप्रैल, 2011

- 1 कीर्ति मठ में चीन की 'देशभक्ति पुनर्शिक्षा' अभियान जारी।
- 2 नाबा काउंटी के जेलेब प्रखंड में सेना एवं पुलिस के अधिकारियों ने घर-घर जाकर तलाशी ली।

19 अप्रैल, 2011

- 1 कीर्ति मठ में चल रहे 'देशभक्ति पुनर्शिक्षा' सत्र के दौरान एक उच्च पदस्थ चीनी अधिकारी ने भिक्षुओं को धमकाया। उसने कहा कि यदि भिक्षु सही तरीके से नहीं रहते हैं तो उसके पास इतना अधिकार और क्षमता है कि वह उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा।
- 2 इसी दिन शाम को पुलिस, सेना और सरकारी अधिकारियों सहित करीब 10

सुरक्षा बलों का जत्था मठ के आसपास गश्त करता रहा और उन्होंने भिक्षुओं से पूछताछ भी की। जिन भिक्षुओं ने उनके हिसाब से सही जवाब नहीं दिया उन्हें बुरी तरह पीटा गया।

- 3 आसपास के भी कई मठों को चेतावनी दी गई और उनके भिक्षुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी गई।
- 4 कीर्ति मठ से सुरक्षा बलों द्वारा भिक्षुओं को जबरन हटाने के विरोध में 60 से 70 साल की उम्र के करीब 200 लोग मठ के बाहर धरने पर बैठ गए।

20 अप्रैल, 2011

- 1 चीन के पड़ोसी प्रांतों से करीब 800 चीनी अधिकारी मठ पहुंचे और उन्होंने विरोध और अशांति को जबरन कुचलने का प्रयास किया। 2 मठ के हर कमरे में करीब 10 सुरक्षा और पुलिस अधिकारी गए। जिन भिक्षुओं ने इन अधिकारियों के सवालों का जवाब नहीं दिया उन्हें बुरी तरह पीटा और प्रताड़ित किया गया। कई लोगों को तो घंटों तक एक पेड़ से लटका कर रखा गया।
- 2 इसके साथ ही इस दमन को दुनिया से छिपा कर रखने के लिए सरकारी अधिकारियों ने दुष्प्रचार भी करना शुरू कर दिया।

21 अप्रैल, 2011

- 1 सभी दूरसंचार नेटवर्क बंद कर दिए गए।
- 2 रात 9 बजे से सुबह 4 बजे के बची चीनी सेना, पुलिस और जन सशस्त्र पुलिस के जवानों ने कीर्ति मठ से करीब 300 भिक्षुओं को गिरफ्तार कर लिया।

- 3 करीब 200 लोगों ने सशस्त्र बलों और पुलिस द्वारा भिक्षुओं की गिरफ्तारी को रोकने का प्रयास किया। इनमें से ज्यादातर लोग 60 साल के ऊपर के थे। इन विरोध करने वाले लोगों को बुरी तरह पीटा गया और दो लोगों की जान चली गई।
- 4 जिन दो लोगों की पिटाई से मौत हो गई उनमें ऊपरी तवा के निवासी 60 वर्षीय डोंको और नाक्तसंगमा के राको सांग हाउस में रहने वाले 65 साल के शेरकी थे।
- 5 इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों को सेना की ट्रकों में भरकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया।

22 अप्रैल, 2011

पुलिस और सेना के वाहनों के अलावा अन्य सभी वाहनों के बाजार में मुख्य सड़क पर आने पर रोक लगा दी गई। पिछली रात को गिरफ्तार ज्यादातर लोगों को सुबह 9 बजे छोड़ा गया, लेकिन युवा कैदियों को रिहा नहीं किया गया।

तिब्बती युवा कांग्रेस के आमरण अनशन का 11वां दिन

(टीवाईसी, 5 मई, नई दिल्ली)

तिब्बती युवा कांग्रेस (टीवाईसी) के तीन कार्यकर्ताओं का जंतर-मंतर पर चल रहा आमरण अनशन गुरुवार को 11वें दिन में प्रवेश कर गया जिसके बाद उनके स्वास्थ्य में काफी गिरावट देखी जा रही है। टीवाईसी के अध्यक्ष सेवांग रिनजिन ने यह जानकारी दी है। सेवांग ने बताया, "यहां तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया है और भूख हड़ताल कर रहे तीनों लोगों की हालत में साफ तौर पर

इस गर्मी में सिर्फ पानी पीकर जिंदा रहना बहुत साहस की बात है। इससे पता चलता है कि वे अपने लक्ष्य के प्रति कितने कष्टसंकल्प और दृढ़ हैं।"

चीनी प्रशासन इस क्षेत्र के विकास के बहाने मठ परिसर पर अपना कब्जा जमा रहा था।

संघ ने
कहा,
"इसके
अलावा
परमपावन
दलाई लामा
ने जिस
तरह से
दुनिया भर
के नेताओं,
सांसदों और
लोकतंत्र
समर्थकों का
मजबूत
समर्थन एवं
प्रशंसा
हासिल की
है

पूर्वी तिब्बत में दो भिक्षुओं को तीन साल तक कारावास की सजा सुनाई गई

"दुनिया
भर की
सरकारें
इस संकट
के बारे में
चिंता
जताते हुए

गिरावट देखी जा रही है। उनको कुछ खाए हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। इस गर्मी में सिर्फ पानी पीकर जिंदा रहना बहुत साहस की बात है। इससे पता चलता है कि वे अपने लक्ष्य के प्रति कितने कप्तसंकल्प और दृढ़ हैं।"

गौरतलब है कि तिब्बत के कीर्ति मठ में चीनी दमन के विरोध में टीवाईसी के तीन अधिकारियों धोनडुप ल्हडार (उपाध्यक्ष), तेनजिन नोरसांग (संयुक्त सचिव) और कोंछोक यांगफेल (वित्त सचिव) ने गत 25 अप्रैल, 2011 से अनशन शुरू किया है। तिब्बत के कीर्ति मठ में चीनी अधिकारियों द्वारा 21 अप्रैल को दो बुजुर्ग तिब्बतियों को पीट-पीट कर मार डाला गया और 300 से ज्यादा भिक्षुओं को गिरफ्तार किया गया है। टीवाईसी ने कीर्ति मठ से चीनी सुरक्षा बलों को तत्काल हटाने की मांग की है और वहां पिछले कई हफ्तों से भिक्षुओं पर थोपे जा रहे तथाकथित 'देशभक्ति पुनर्शिक्षा' अभियान को तत्काल बंद करने की मांग की है। तिब्बती युवा कांग्रेस अपना एक प्रतिनिधिमंडल चीन भेजना चाहता है ताकि तिब्बत के भीतर के राजनीतिक कैदियों की सही हालत का पता लग सके।

(टिबेट डॉट नेट, 4 मई, धर्मशाला)

पूर्वी तिब्बत के खम प्रांत में स्थित चामदो के जोमदा क्षेत्र में चीन सरकार द्वारा अपने मठ की जमीन पर कब्जा करने का विरोध कर रहे दो भिक्षुओं को जेल में डाल दिया गया है। धर्मशाला स्थित एक मानवाधिकार संगठन ने यह जानकारी दी है।

तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र (टीसीएचआरडी) ने 2 मई को जारी एक बयान में बताया, "एक स्थानीय चीनी अदालत

ने इस साल मार्च में जोफु मठ के दो भिक्षुओं टुल्कु जांगछुब और पेसांग को क्रमशः तीन और ढाई साल कारावास की सजा सुनाई। 25 साल के टुल्कु जांगछुब को दिसंबर, 2009 में जोफु मठ परिसर पर चीनी अधिकारियों के नियंत्रण के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चीनी प्रशासन इस क्षेत्र के विकास के बहाने मठ परिसर पर अपना कब्जा जमा रहा था। टीसीएचआरडी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस प्रदर्शन के दौरान टुल्कु मठ के अन्य भिक्षु और स्थानीय जनता ने मांग की कि उक्त जमीन मठ की है और वह मठ के पास ही रहनी चाहिए। पेसांग को जनवरी 2011 में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जोमदा के कारावास में रखा गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उन्हें जल्दी ही पोवो ट्रामो की जेल में भेजा जाएगा।

नाबा में दो तिब्बती गिरफ्तार, भिक्षुओं के वापस जाने पर रोक

(धर्मशाला, 16 मई)

चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के नाबा काउंटी में स्थित कीर्ति मठ से 6 मई को एक और तिब्बती भिक्षु को गिरफ्तार कर लिया है। एक तिब्बती सूत्र ने यह जानकारी दी है। 39 साल के भिक्षु लोबसांग खेदुप को उनके मठ में स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया लेकिन न तो उनकी गिरफ्तारी की वजह बताई गई और न ही इस बात का पता चल पाया है कि उन्हें कहां रखा गया है।

इस घटना के दो माह पहले 19 मार्च को एक 60 साल के तिब्बती भिक्षु गेरिक को गिरफ्तार किया गया था, इसके एक दिन बाद ही निर्वासित तिब्बतियों को अपने प्रधानमंत्री और निर्वासित संसद का चुनाव करना था। मेरुआमा टाउनशिप के चारागाह मंडल 3 में रहने वाले

गे-सांग परिवार से जुड़े गेरिक पर यह आरोप लगाया गया कि वे साल 2008 से ही नाबा की परिस्थिति के बारे में बाहरी दुनिया को जानकारी दे रहे हैं और खासकर इस साल मार्च में कीर्ति मठ के भिक्षु फुंत्सोक के आत्मदाह की खबरें उन्होंने दुनिया भर को पहुंचाई।

आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के चीनी-तिब्बती मैत्री संघों ने नए कालोन ट्रिपा को बधाई दी

(टिबेट डॉट नेट, 2 मई, कैनबरा)
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के चीनी-तिब्बती मैत्री संघ और चीन में लोकतंत्र के समर्थकों ने तिब्बती जनता द्वारा नए कालोन ट्रिपा चुने जाने पर डॉ. लोबसांग सेंगे को बधाई दी है। मैत्री संघ ने 30 अप्रैल को कैनबरा के तिब्बत कार्यालय को भेजे बधाई संदेश में कहा है, "चीन में लोकतंत्र के समर्थक और ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के चीनी-तिब्बती मैत्री संघ तिब्बतियों द्वारा लोकतांत्रिक चुनावों के द्वारा नए कालोन ट्रिपा चुने जाने पर डॉ. लोबसांग सेंगे को हार्दिक बधाई देते हैं।" उन्होंने इस चुनाव की तारीफ करते हुए कहा कि यह सैकड़ों सालों के सरकार के पुराने परंपरागत व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव है और तिब्बती जनता द्वारा लोकतंत्र की दिशा में लगातार आगे बढ़ने का कदम है। संघ ने लोकतंत्र, मानवाधिकार और तिब्बती समाज को एक सकारात्मक भविष्य की ओर ले जाने की दिशा में तिब्बतियों द्वारा किए जा रहे महान प्रयासों की तारीफ की।

संघ ने कहा, "इसके अलावा परमपावन दलाई लामा ने जिस तरह से दुनिया भर के नेताओं, सांसदों और लोकतंत्र समर्थकों का मजबूत समर्थन एवं प्रशंसा हासिल की है उससे केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी स्थान हासिल करने और निर्वासित

तिब्बती समुदाय में आधुनिक लोकतंत्र लाने में मदद मिली है।

कीर्ति मठ दिवस' मनाएगा भारत का कोर ग्रुप फॉर टिबेटन कॉज

(टिबेट डॉट नेट, 3 मई, नई दिल्ली)

उत्तर-पूर्वी तिब्बत के कीर्ति मठ में चीन सरकार के दमन पर चर्चा करने के लिए भारत में कोर ग्रुप फॉर टिबेटन कॉज के अधिकारी तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मिले। कोर ग्रुप फॉर टिबेटन कॉज के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. नंदकिशोर त्रिखा और भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री एस. पी. मालवीय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा से मुलाकात कर उन्हें तिब्बत में बिगड़ते हालात की जानकारी दी।

यशवंत सिन्हा ने तिब्बत के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताई और तिब्बती जनता के प्रति अपना पूरा समर्थन जताया। कोर ग्रुप फॉर टिबेटन कॉज ने यह निर्णय लिया है कि संगठन कीर्ति मठ के भिक्षु फुंत्सोक के निधन को याद करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में एक दिन 'कीर्ति मठ दिवस' के रूप में मनाएगा। गौरतलब है कि तिब्बत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के चीन सरकार द्वारा बर्बर दमन के विरोध में कीर्ति मठ के युवा भिक्षु फुंत्सोक ने आत्मदाह कर लिया था।

ताइवान के तिब्बत समर्थक समूहों और एनजीओ ने कीर्ति मठ का मसला उठाया

(टिबेट डॉट नेट, 5 मई, ताइपेई)

ताइवान की संसद सदस्य और लंबे समय से तिब्बत समर्थक रहीं सुश्री तियान क्यूई जिन ने ताइपेई के तिब्बत समर्थक समूहों के प्रतिनिधिमंडल और एक शीर्ष ताइवानी अधिकारी के बीच 4 मई को एक बैठक

उन्होंने यह भी मांग की कि इन 300 भिक्षुओं को तत्काल रिहा किया जाए और मीडिया को इस इलाके की सही स्थिति की रिपोर्ट करने की इजाजत मिले।

300 भिक्षुओं को तत्काल रिहा किया जाए

(1)



(2)



(10)



कैमरे की आंख

1. कैलिफोर्निया के लांग बीच में स्थित कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में 4 मई, 2011 को अवॉर्ड हासिल करते परमपावन दलाई लामा। फोटो: डॉन फार्बर
2. टीवाईसी के अनिश्चितकालीन अनशन स्थल नई दिल्ली के जंतर-मंतर (15 मई, 2011) रिनपोछे और उनके सहकर्मी तेम्पा सेरिंग को अनशन के बारे में जानकारी देते हुए।
3. धर्मशाला स्थित टीसीवी स्कूल के ऑडिटोरियम में 21 मई, 2011 को आयोजित दूसरे
4. धर्मशाला के मुख्य मंदिर सुगलांगखांग में 4 मई, 2011 को प्रार्थना करते ग्यालवांग क
5. डिप्टी स्पीकर खेनपो सोनम तेनफेल
6. नई दिल्ली में 29 अप्रैल, 2011 को यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात करता ति
7. दिल्ली के जंतर मंतर पर 25 अप्रैल से ही टीवाईसी के तीन अधिकारी अनशन पर बैठे हु
- देते टीवाईसी के अध्यक्ष सेवांग रिनजिन। फोटो: टीवाईसी
8. ताइवान के शहर ताइछुंग के सिंग विश्वविद्यालय में 26 मई, 2011 को व्याख्यान देते
9. तिब्बत प्रशासन के धर्म एवं संस्कृति विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी ख
- जिनका अपने चार कर्मचारियों के साथ एक दुःखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो ग
- सभा में उनके अच्छे पुनर्जन्म की कामना की गई। नामग्याल मठ के अध्यक्ष ने इस प्रा
- सभा के दौरान तिब्बतियों ने स्वर्गीय मुख्यमंत्री और उनके कर्मचारियों के परिवार की
10. स्पीकर पेनपा सेरिंग



(9)



(8)

आंखों देखी

(3)



(4)



मेरे की आंख से

में 4 मई, 2011 को आयोजित एक समारोह में एमनेस्टी इंटरनेशनल का 'शाइन अ लाइट'

मंतर (15 मई, 20011) पर टीवाईसी के अध्यक्ष सेवांग रिनजिन तिब्बत के प्रधानमंत्री सामदोंग जानकारी देते हुए।

को आयोजित दूसरे तिब्बती राष्ट्रीय आम सभा का शुरुआती सत्र।

करते ग्यालवांग करमापा।

मुलाकात करता तिब्बती संसद का प्रतिनिधिमंडल।

री अनशन पर बैठे हुए हैं। इस बारे में निर्वाचित तिब्बती मुख्यमंत्री लोबसांग सेंगे को जानकारी

को व्याख्यान देते परमपावन दलाई लामा के प्रतिनिधि दावा सेरिंग (दाएं)।

मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष प्रार्थना का आयोजन किया टना में निधन हो गया था। धर्मशाला के मुख्य मंदिर सुगलागखांग में आयोजित इस प्रार्थना के अध्यक्ष ने इस प्रार्थना सभा की अगुवाई की और इसमें सैकड़ों तिब्बती शामिल हुए। इस रियों के परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना की।

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(5)



(7)

(6)

इसके बाद 3 जून को राष्ट्रीय ताम कांग विश्वविद्यालय ने भी एक व्याख्यान का आयोजन किया है।

यूरोपीय संघ की प्रतिनिधि एश्टॉन ने कीर्ति मठ की परिस्थिति पर चिंता जताई

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बतियों का लगातार हिंसक दमन किया जा रहा है।

करवाई। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल तिब्बती स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों ने ताइवान के मुख्य भूमि मामलों की परिषद के उपाध्यक्ष श्री झाओ जियान मिन के साथ मुलाकात के दौरान उत्तर-पूर्वी तिब्बत के कीर्ति मठ में चीन सरकार द्वारा जारी दमन के मसले को उठाया। श्री झाओ को दिए पत्र में प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान सरकार से अनुरोध किया कि वे चीन सरकार को इस बात के लिए राजी करें कि वह कीर्ति मठ से सैन्य घेराबंदी हटाए जिसकी वजह से 2 तिब्बती मारे गए हैं और 300 से ज्यादा भिक्षुओं को जेल में ठूस दिया गया है। उन्होंने यह भी मांग की कि इन 300 भिक्षुओं को तत्काल रिहा किया जाए और मीडिया को इस इलाके की सही स्थिति की रिपोर्ट करने की इजाजत मिले।

(तिब्बत ब्यूरो, ब्रुसेल्स, 18 मई)
यूरोपीय संघ में विदेशी एवं सुरक्षा नीति की उच्च प्रतिनिधि लेडी एश्टॉन ने तिब्बत के नाबा क्षेत्र में स्थित कीर्ति मठ के हालात पर पहली बार चिंता जताई है। पिछले महीने यूरोपीय संसद के सदस्य प्रोवेरा ने उनसे मिलकर यह अनुरोध किया था कि वे तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने लिए वहां जारी दमन की कड़ी आलोचना करें। इसके बाद अब प्रोवेरा को लिखे पत्र में एश्टॉन ने कहा है, "मैं मठ में भिक्षुओं की मौत, पिटाई और बड़े पैमाने पर जेल भेजे जाने की खबरों से काफी चिंतित हूं। बीजिंग स्थित यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने इस घटना के बारे में तथ्य जुटाने के प्रयास किए हैं, लेकिन वे इसमें असमर्थ रहे क्योंकि ऐसा लगता है कि चीनी अधिकारियों ने मठ को चारों तरफ से सील कर दिया है और उस

इलाके से सभी विदेशी लोगों को बाहर कर दिया गया है। इसके बावजूद प्रतिनिधिमंडल जमीनी स्तर पर इस घटना के बारे में और सूचनाएं हासिल करने की कोशिश कर रहा है।" यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि ने कहा, "यूरोपीय संघ ने लगातार चीनी अधिकारियों से यह निवेदन किया है कि सभी तिब्बतियों को अपने धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों के पालन की इजाजत दी जाए।

तिब्बत समर्थक समूहों ने कीर्ति मठ संकट पर दुनिया भर के नेताओं से किया निवेदन

(टिबेट डॉट नेट, 28 मई, धर्मशाला)
दुनिया के छह महाद्वीपों के 183 से ज्यादा तिब्बत समर्थक समूहों के गठबंधन अंतरराष्ट्रीय तिब्बत नेटवर्क (आईटीएन) ने दुनिया की सभी सरकारों को एक आपात संदेश भेजकर यह निवेदन किया है कि चीन सरकार से यह बात सख्ती से कहें कि वह उत्तर-पूर्वी तिब्बत के कीर्ति मठ में दमन को खत्म करे। इस निवेदन पर तिब्बत आंदोलन से जुड़े 200 से ज्यादा संगठनों के हस्ताक्षर हैं। इसमें निवेदन किया गया है कि, "दुनिया भर की सरकारें इस संकट के बारे में चिंता जताते हुए एक सार्वजनिक बयान जारी करें और इस मसले को सख्त राजनयिक तरीकों से चीन के सामने उठाते रहें।"

संगठनों ने दुनिया भर के नेताओं से अनुरोध किया है कि वे चीन तक यह संदेश पहुंचाएं कि वह तत्काल नाबा से सुरक्षा बलों को हटाए, सभी बंदियों को बिना किसी शर्त के रिहा करे और वहां अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और मीडिया को बिना किसी रोक-टोक के जाने दे। उत्तर-पूर्वी तिब्बत की हालत को सबके सामने लाने के लिए आईटीएन ने 'ग्लोबल वीक ऑफ एक्शन फॉर नाबा' नाम से एक समन्वित अभियान शुरू किया है।

छुंग सिंग विश्वविद्यालय में तिब्बती लोकतंत्र पर व्याख्यान

(टिबेट डॉट नेट, 30 मई, ताइपेई)

ताइवान में परमपावन दलाई लामा के प्रतिनिधि श्री दावा सेरिंग को गत 26 मई को ताइछुंग स्थित राष्ट्रीय छुंग सिंग विश्वविद्यालय में तिब्बती लोकतंत्र पर एक व्याख्यान देन के लिए आमंत्रित किया गया। दो घंटे तक चले इस व्याख्यान के दौरान प्रतिनिधि दावा सेरिंग ने तिब्बती इतिहास, उसके आधुनिक लोकतंत्र और हाल में तीसरे कालोन ट्रिपा के ऐतिहासिक चुनाव का ब्यौरा दिया। उन्होंने श्रोताओं को यह भी बताया कि किस तरह से निर्वासित तिब्बती समुदाय के लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में बदलाव आ रहे हैं। इस व्याख्यान को सुनने के लिए विश्वविद्यालय के करीब 60 विद्यार्थी भी मौजूद थे। श्री दावा सेरिंग को यह देखकर खुशी हुई कि विद्यार्थी काफी तन्मयता से उनकी बात को सुन रहे थे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय छुंग विश्वविद्यालय केंद्रीय ताइवान के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। इसके बाद 3 जून को राष्ट्रीय ताम कांग विश्वविद्यालय ने भी एक व्याख्यान का आयोजन किया है।

नाबा के कीर्ति मठ में तनाव बढ़ा, तिब्बती संसद ने दुनिया से की अपील

(टिबेट डॉट नेट, नई दिल्ली, 3 मई)

तिब्बत के नाबा काउंटी में तनाव बढ़ने को देखते हुए डिप्टी स्पीकर डोलमा ग्यारी के नेतृत्व में निर्वासित तिब्बती संसद के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली स्थित विदेशी दूतावासों से संपर्क कर उनसे इस संकट को दूर करने के लिए मदद मांगी है। इस प्रतिनिधि मंडल में सुश्री ग्यारी के अलावा तीन सांसद श्री कालसांग ग्यालत्सेन, वेन सोनम तेमफेल और श्रीमती सेरिंग युडोन शामिल थे।

विभिन्न दूतावासों के राजदूतों को लिखे पत्र में इस प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि वह उत्तर-पूर्वी तिब्बत के नाबा में स्थित कीर्ति मठ में अपना तथ्यान्वेषी दल भेजें ताकि वहां मानवाधिकार की रक्षा और स्थिति को सामान्य होने में मदद मिल सके।

विदेशी सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया कि वह नाबा सहित तिब्बत के अन्य हिस्सों में भी स्वतंत्र मीडिया के दौरे को समर्थन दें। प्रतिनिधिमंडल ने इन देशों से यह भी कहा कि वे चीन सरकार से यह भी अनुरोध करें कि वह गिरफ्तार किए गए भिक्षुओं को रिहा करे और मठ को अपनी धार्मिक गतिविधियां चलाने की इजाजत दे। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बतियों का लगातार हिंसक दमन किया जा रहा है। पत्र में कहा गया है, “देगे के जोमदा क्षेत्र में रहने वाले बुलुग को 25 मार्च, 2011 को मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया गया, प्रताड़ित किया गया और उनकी मौत हो गई। इसी प्रकार 3 अप्रैल, 2011 को ताशिकिल के आमदो लाबरंग में जामयांग जिनपा की मौत हो गई। चीनी अधिकारियों द्वारा अमावनीय रवैए से हुई मौतों को ये हालिया उदाहरण हैं।”

अरुणाचल के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की आकस्मिक मौत पर कशग को गहरा दुःख

(टिबेट डॉट नेट, 4 मई, धर्मशाला)

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कशग ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू के दुःखद निधन पर शोक जताया है। खांडू का तवांग जिले के पास लोबोथंग में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। अपने शोक संदेश में कालोन ट्रिपा प्रोफेसर सामदोंग रिनपोछे ने कहा, “एक युवा, ईमानदार

कालोन
ट्रिपा ने
कहा,
“उनकी
मौत
तिब्बतियों
और
अरुणाचल
की जनता,
दोनों के
लिए भारी
क्षति है,
इसलिए मैं
अपने
मंत्रिमंडल
के अन्य
सहयोगियों
के साथ
उनके
परिवार
जनों और
राज्य की
जनता के
लिए प्रार्थना
करते हैं
और हृदय
से शोक
संवेदना
प्रकट करते
हैं।”

“मैं यह साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि मैं भारत में चीनी जासूस, एजेंट या उसका बिठाया आदमी नहीं हूँ।”

और अरुणाचल के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में से एक दोरजी खांडू के दुःखद निधन पर हम गहरी व्यथा और चिंता जाहिर करते हैं। उन्होंने शांति एवं सौहार्दपूर्वक रहने वाले अरुणाचल के लोगों और तिब्बती लोगों के जीवन में भारी सुधार और विकास किया था।”

कालोन ट्रिपा ने कहा, “उनकी मौत तिब्बतियों और अरुणाचल की जनता, दोनों के लिए भारी क्षति है, इसलिए मैं अपने मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों के साथ उनके परिवार जनों और राज्य की जनता के लिए प्रार्थना करते हैं और हृदय से शोक संवेदना प्रकट करते हैं।”

कालोन ट्रिपा ने कहा कि निर्वासित सरकार के धर्म एवं संस्कृति विभाग द्वारा 5 मई को धर्मशाला के मुख्य मंदिर सुगलागखांग में एक विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जाएगा।

कीर्ति मठ के शहीद भिक्षु के लिए ग्यालवांग करमापा ने प्रार्थना की

एमनेस्टी इंटरनेशन ने अपना पहला 'शाइन अ लाइट अवॉर्ड' परमपावन दलाई लामा को दिया है।

(टिबेट डॉट नेट, धर्मशाला, 5 मई)

परम श्रेष्ठ 17वें ग्यालवांग करमापा ओग्येन ट्रिनले दोरजी ने कीर्ति मठ के एक भिक्षु फुंत्सोक के निधन के 49वें दिन पर आयोजित विशेष प्रार्थना सभा की अध्यक्षता की। कीर्ति मठ के भिक्षु फुंत्सोक ने चीनी दमन के विरोध में इस साल 16 मार्च को आत्मदाह कर लिया था। सुबह के समय आयोजित इस प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने वाले सैकड़ों तिब्बतियों ने भी तिब्बत आंदोलन के लिए अपना जीवन बलिदान कर देने वाले सभी तिब्बतियों के लिए प्रार्थना की।

तिब्बती राष्ट्रीय महासभा की ऐतिहासिक बैठक

(टिबेट डॉट नेट, 21 मई, धर्मशाला)

दुनिया भर के तिब्बती समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सैकड़ों तिब्बती प्रतिनिधियों ने यहां परमपावन दलाई लामा के प्रशासनिक एवं राजनीतिक अधिकार और जिम्मेदारियां केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के चुने हुए नेता को सौंपने के लिए चार्टर में संशोधन पर विचार-विमर्श किया। तिब्बती राजव्यवस्था को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बनाने के लिहाज से परमपावन दलाई लामा ने अपनी औपचारिक सत्ता छोड़ने का निर्णय लिया है जिसे देखते हुए यह बैठक बुलाई गई है।

तिब्बती संसद के अध्यक्ष पेनपा सेरिंग ने बैठक के उद्घाटन भाषण में कहा कि इस बैठक में मौजूद प्रतिनिधि चार्टर में एक नई प्रस्तावना, अनुच्छेद 1 और अन्य संबंधित 39 अनुच्छेदों को शामिल करने पर विचार करेंगे जिसे चार्टर संशोधन प्रारूप समिति ने तैयार किए हैं। प्रारूप समिति ने 39 अनुच्छेदों में संशोधन किया है जिसमें चार्टर में परमपावन को सौंपे गए कार्यकारी शक्तियों से जुड़ा अनुच्छेद 19 भी है। संशोधनों के मुताबिक चार्टर में परमपावन को दी गई 9 कार्यकारी शक्तियों को चुने हुए नेतृत्व और तिब्बती लोकतंत्र के तीन स्तंभों को सौंपा जाएगा।

परमपावन दलाई लामा के औपचारिक सत्ता त्यागने के लिए संसद ने किया चार्टर में संशोधन

(टिबेट डॉट नेट, 29 मई, धर्मशाला)

अपने अतिरिक्त सत्र में तीन दिन तक गहर विचार-विमर्श के बाद आखिरकार 14वीं निर्वासित तिब्बती संसद ने इस बात पर मुहर लगा दी कि परमपावन दलाई लामा के प्रशासनिक व राजनीतिक अधिकार लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए तिब्बती नेता को

सौंप दिए जाएं। संसद की मंजूरी के लिए रविवार को यह संशोधन प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा गया। अपनी मंजूरी के बाद परमपावन वे सारी शक्तियां अब पूरी तरह से सीटीए और निर्वाचित नेता को सौंप देंगे जो पहले संयुक्त रूप से उनके और सीटीए के पास थीं। अब समूची तिब्बती जनता का प्रतिनिधित्व और सेवा सीटीए करेगा।

26 से 28 मई तक चले अतिरिक्त सत्र के दौरान संसद ने एक नए प्रस्तावना और चार्टर के अनुच्छेद 1 के तहत परमपावन को मिले सहज अधिकारों और जिम्मेदारियों पर मुहर लगा दी।

इस प्रस्तावना में इस बात को रेखांकित किया गया है कि, "केंद्रीय तिब्बती प्रशासन समूचे तिब्बती जनता का वैधानिक शासन निकाय और प्रतिनिधि बना रहेगा।" इसमें इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि तिब्बत 200 ईसा पूर्व से साल 1951 तक एक संप्रभु राष्ट्र रहा जब तक कि चीन जनवादी गणतंत्र ने इस पर हमला नहीं किया था। इसमें परमपावन दलाई लामा के साल 1959 में भारत आने के बाद उनके द्वारा शुरू किए जाने वाले लोकतांत्रिक सुधारों के प्रयासों को भी रेखांकित किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार परमपावन दलाई लामा तिब्बत और तिब्बती जनता के 'संरक्षक और प्रतीक हैं।'

पेनपा सेरिंग को स्पीकर और खेनपो सोनम तेनफेल को डिप्टी स्पीकर चुना गया

(टिबेट डॉट नेट, 30 मई, धर्मशाला)
केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुख्य चुनाव आयुक्त ने श्री पेनपा सेरिंग को 15वीं निर्वासित तिब्बती संसद का अध्यक्ष—स्पीकर—और खेनपो सोनम तेनफेल को उपाध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की है। चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को संसद सदस्यों के बीच कराए गए एक

गुप्त मतदान में 22 मत हासिल कर श्री पेनपा सेरिंग स्पीकर निर्वाचित हुए, जबकि निंगमा बौद्ध स्कूल से संसद सदस्य खेनपो सोनम तेनफेल 20 मत हासिल कर डिप्टी स्पीकर चुने गए। श्री पेनपा सेरिंग इसके पहले 14वीं तिब्बती संसद के आधे कार्यकाल पूरा होने के बाद भी स्पीकर बने थे। अब मंगलवार को मुख्य न्याय आयुक्त संसद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को शपथ दिलाएंगे। इसके पहले 15वीं संसद के निर्वाचित सदस्य संसद भवन में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे।

शीर्ष तिब्बती भिक्षु ने चीनी 'जासूस' होने के आरोप का जोरदार खंडन किया

(एएफपी, 2 मई)

तिब्बतियों के शीर्ष बौद्ध भिक्षुओं में से एक करमापा लामा ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है कि वह चीनी जासूस हैं। नई दिल्ली में सोमवार को इस बारे में पहली बार टिप्पणी करते हुए 26 साल के करमापा ने कहा, "मैं यह साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि मैं भारत में चीनी जासूस, एजेंट या उसका बिठाया आदमी नहीं हूँ।" करमापा 14 साल की उम्र में ही तिब्बत से निर्वासित होकर भारत आ गए थे। इस साल की शुरुआत में भारतीय मीडिया ने प्रतिरक्षा सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें चलाई थीं कि करमापा लामा भारत में चीन समर्थक मठों की स्थापना के लिए भेजे गए चीनी एजेंट हो सकते हैं। यह आरोप तब सामने आए जब अधिकारियों ने करमापा के निवास ग्युतो मठ से चीनी युआन सहित 400 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की विदेशी मुद्राएं बरामद कीं। उनके कर्मचारियों ने कहा कि इन अफवाहों पर विराम लगाने के लिए इस दुर्लभ संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया है। करमापा

*करमापा
14 साल
की उम्र में
ही तिब्बत
से
निर्वासित
होकर
भारत आ
गए थे।*

*एयरपोर्ट
पर
पत्रकारों से
बात करते
हुए सेंगे ने
कहा कि
वह दलाई
लामा को
उनकी
मातृभूमि
तिब्बत के
ल्हासा ले
जाने के
लिए
प्रतिबद्ध
हैं।*

बहुत कम मौकों पर अब तक प्रेस के सामने गए हैं।

परमपावन दलाई लामा को पहला 'शाइन अ लाइट अवॉर्ड'

(टिबेट डॉट नेट, 5 मई, लांग बीच)

"शायद महात्मा गांधी ने भी इसी तरह के सवालों का सामना किया होगा, जब वह पहली बार स्वतंत्रता संग्राम में उतरे होंगे और उस समय उन्होंने जरूर यह कहा होगा कि वह भारत को एक आज़ाद देश बनाएंगे।"

एमनेस्टी इंटरनेशन ने अपना पहला 'शाइन अ लाइट अवॉर्ड' परमपावन दलाई लामा को दिया है। लांग बीच में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के कारपेंटर परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर में आयोजित एक समारोह में परमपावन को यह अवॉर्ड दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के 1000 से ज्यादा अतिथियों और सदस्यों ने परमपावन का भव्य स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका से आई सुश्री एन बुरोग्स ने स्वागत भाषण पढ़ा। एमनेस्टी इंटरनेशनल अमेरिका के कार्यकारी निदेशक श्री लैरी कॉक्स ने तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल की भूमिका का एक सामान्य विवरण पेश किया। उन्होंने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर "उन लोगों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है जिनके जीवन, शब्द और कार्य ने हमें प्रेरित किया है, चुनौती दी है और आगे बढ़ाया है कि हम कभी भी अपने कार्यों को जारी रखना, अपने अहिंसक कार्यों को बढ़ाना न छोड़े उस आज़ादी और गरिमा के लिए जिस पर हर मानव का अधिकार है।" श्री कॉक्स ने परमपावन 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो की तारीफ करते हुए उन्हें शांति का प्रतीक और अहिंसा का पुरोधा बताया। श्री कॉक्स और एमनेस्टी के छात्र समूह के तीन सदस्यों ने परमपावन को अवॉर्ड से सम्मानित किया। परमपावन ने अपने विवेक के साथ एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए जो अतुलनीय योगदान दिया है, यह अवॉर्ड उसको स्वीकृति देता है। इस अवॉर्ड का डिजाइन तिब्बती कलाकार तेनजिन

मोछोए ने तैयार किया और इसका मॉडल 'दलाई लामा' की पदवी पर आधारित है जिसका मतलब होता है 'ज्ञान का महासागर'। कॉक्स ने कहा, "इसमें दिख रही छोटी लहर परमपावन के अविरल करुणा की संभावना और पहुंच तथा इस दुनिया को बदलने में हर मानव की संभावना को प्रदर्शित करती है।"

दलाई लामा ने चीन में राजनीतिक सुधारों का आह्वान किया

(फायूल डॉट कॉम, 9 मई, मिनापोलिस) तिब्बती नेता दलाई लामा ने चीन में राजनीतिक सुधार करने का आह्वान किया है और शिक्षित चीनी युवाओं से अनुरोध किया है कि वे चीन के भविष्य के निर्माण में सक्रियता से भूमिका निभाएं। मिनापोलिस में शनिवार को बौद्ध धर्म पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने यह बात कही। इस सेमिनार के दौरान उन्होंने करीब सैकड़ों चीनी विद्यार्थियों से भी मुलाकात की जिन्होंने उनसे बौद्ध धर्म से लेकर चीन-तिब्बत संबंधों के बारे में कई सवाल किए।

दलाई लामा ने कहा कि यद्यपि चीन में निकट भविष्य में लोकतंत्र का आना संभव नहीं दिख रहा, लेकिन चीनी अधिकारियों को वहां ज्यादा आज़ादी देनी चाहिए और वहां डर का जो मौजूदा माहौल बना हुआ है उससे लोगों का भरोसा नहीं जीता जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि चीन सरकार को 'खुलापन, ईमानदारी और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर चलना चाहिए यदि वह चाहती है कि चीन का दुनिया के देशों के नजर में ज्यादा सम्मानजनक स्थान हासिल हो। उन्होंने इस बात को भी दुहराया कि वह 'चीन में धीरे-धीरे बदलाव का समर्थन करते हैं, न कि रातों-रात बदलाव का क्योंकि अचानक हुए राजनीतिक परिवर्तन से वहां अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है।'

तिब्बत के निर्वाचित प्रधानमंत्री अनशनकारियों से मिले

(डब्ल्यूएसजे ब्लॉग, 13 मई, नई दिल्ली) निर्वासित तिब्बती सरकार के निर्वाचित प्रधानमंत्री (कालोन ट्रिपा) डॉ. लोबसांग सेंगे ने गुरुवार को तिब्बती युवा कांग्रेस के उन तीन अधिकारियों से मुलाकात की जो चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत के नाबा काउंटी में स्थित कीर्ति मठ में चलाए जा रहे दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं।

अब 18वें दिन में पहुंच चुका तिब्बती युवा कांग्रेस का यह अनशन इस मांग को लेकर है कि मठ से चीनी सुरक्षा बलों को तत्काल हटाया जाए और हाल में नाबा में गिरफ्तार हुए लोगों सहित सभी राजनीतिक बंदियों की तत्काल रिहाई की जाए। तिब्बती युवा कांग्रेस यह भी मांग कर रही है कि उसके एक प्रतिनिधिमंडल को तिब्बत जाने की इजाजत दी जाए ताकि वे वहां के राजनीतिक कैदियों की सही हालत का अंदाजा लगा सकें। निर्वाचित तिब्बती प्रधानमंत्री ने जंतर-मंतर पर एक टेंट के नीचे बैठे तिब्बती अनशनकारियों से मिलने के बाद पत्रकारों से कहा, "मैं यहां अपना एकता दिखाने और तिब्बती जनता की तरफ से धन्यवाद देने आया हूं और उन्हें यह बताने भी आया हूं कि हम सब उनके साथ हैं।"

डॉ. लोबसांग सेंगे का भव्य स्वागत (टीएनएन, 13 मई, धर्मशाला)

अमेरिका से यहां के गगल एयरपोर्ट पहुंचने पर तिब्बत के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री लोबसांग सेंगे का भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष छिमे यूंगडुंग, कशग के प्रतिनिधि और कई अन्य प्रख्यात व्यक्तियों सहित बड़ी संख्या में उपस्थित तिब्बती लोगों ने परंपरागत

खातक, अगरबत्ती, गुलदस्तों और तिब्बती झंडों के साथ सेंगे का स्वागत किया। हार्वर्ड के विद्वान डॉ. सेंगे यहां शुक्रवार दोपहर को पहुंचे।

एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए सेंगे ने कहा कि वह दलाई लामा को उनकी मातृभूमि तिब्बत के ल्हासा ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दलाई लामा की नीतियों को आगे बढ़ाने का वादा करते हुए सेंगे ने कहा कि वह उसी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करेंगे 'जो दलाई लामा ने हम सबके लिए तय किया है।'

अपनी प्राथमिकता के बारे में पूछे गए एक सवाल पर वह तिब्बत को फिर से आज़ाद कराएंगे। उन्होंने कहा, "शायद महात्मा गांधी ने भी इसी तरह के सवालों का सामना किया होगा, जब वह पहली बार स्वतंत्रता संग्राम में उतरे होंगे और उस समय उन्होंने जरूर यह कहा होगा कि वह भारत को एक आज़ाद देश बनाएंगे। आज मैं ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहा हूं।" उन्होंने कहा कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन के साथ आज़ादी की वार्ता को आगे बढ़ाना है और उनका एजेंडा तिब्बतियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। गौरतलब है कि निर्वासित तिब्बती सरकार चीन से लगातार वार्ता की कोशिश करती रही है, लेकिन दलाई लामा के दूतों के साथ इस तरह की पिछली नौ वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकला है। सेंगे ने कहा, "हम चीन सरकार के साथ किसी भी समय और कहीं भी बात करने को तैयार हैं।"

नए तिब्बती नेता से बात नहीं करेगा चीन (बीबीसी, 14 मई)

चीन ने निर्वासित तिब्बती सरकार के नए प्रधानमंत्री लोबसांग सेंगे से बात करने से इनकार कर दिया है। तिब्बती वार्ताकारों के

गौरतलब है कि प्रोफेसर सामदोंग रिनपोछे युवा अवस्था में खुद भी तिब्बती युवा कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं। उन्होंने कशग (तिब्बती मंत्रिमंडल) द्वारा लिखित एक पत्र उन कार्यकर्ताओं को सौंपा और उनसे अनशन खत्म करने को कहा।

“मैं कुछ समय पहले परमपावन दलाई लामा से मिला था और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं धर्मशाला आकर उनसे मिलूंगा और आईपीएल ने मुझे इस बात का मौका दिया।”

तिब्बती प्रधानमंत्री रिनपोछे ने टीवाईसी से अनशन खत्म करने का आह्वान किया

हालांकि, दलाई लामा तिब्बतियों के आध्यात्मिक नेता बने रहेंगे।

संपर्क में रहने वाले एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि चीन सिर्फ दलाई लामा के प्रतिनिधियों से ही मुलाकात करेगा। चीन की सरकारी मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में झू वीक्युन ने कहा कि निर्वासित सरकार एक अवैध समूह है जिसकी कोई मान्यता नहीं है। गौरतलब है कि पिछले महीने पूरी दुनिया के निर्वासित तिब्बतियों ने श्री सेंगे को अपना नेता चुना है। सेंगे को दलाई लामा अपने राजनीतिक अधिकार सौंपेंगे।

दलाई लामा ने मार्च माह में कहा था कि वह अपने राजनीतिक अधिकार चुने हुए नेता को सौंपना चाहते हैं। दलाई लामा ने कहा था कि इस तरह का कदम तिब्बती जनता के हित में है। हालांकि, दलाई लामा तिब्बतियों के आध्यात्मिक नेता बने रहेंगे। जानकारों का कहना है कि दलाई लामा यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यदि चीन सरकार खुद अगला दलाई लामा चुनने की कोशिश करती है तो भी तिब्बतियों के पास एक चुना हुआ नेता हो जिस पर वे निर्भर रह सकें और जो चीन और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण से बाहर हो।

(फायूल डॉट कॉम, नई दिल्ली, 16 मई)
निर्वासित तिब्बती सरकार के कालोन ट्रिपा ने राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे तिब्बती युवा कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं से रविवार को मुलाकात की। पूर्व शिक्षाविद और प्रवासी तिब्बतियों द्वारा पहली बार सीधे चुने गए प्रधानमंत्री रिनपोछे ने अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य को लेकर परमपावन दलाई लामा की चिंता से उनको अवगत कराया। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी तेनपा सेरिंग के साथ आए कालोन ट्रिपा ने खुद भी अनशन पर

बैठ कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। गौरतलब है कि प्रोफेसर सामदोंग रिनपोछे युवा अवस्था में खुद भी तिब्बती युवा कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं। उन्होंने कशग (तिब्बती मंत्रिमंडल) द्वारा लिखित एक पत्र उन कार्यकर्ताओं को सौंपा और उनसे अनशन खत्म करने को कहा। आगामी अगस्त माह में सामदोंग रिनपोछे की जगह अगले प्रधानमंत्री डॉ. लोबसांग सेंगे लेंगे जो 20 मार्च को खत्म हुए चुनावों में विजयी हुए हैं।

तिब्बत के हालात पर चर्चा के लिए परमपावन दलाई लामा से मिले आडवाणी

(टिबेट डॉट नेट, 30 मई, धर्मशाला)
भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने सोमवार को धर्मशाला के अपने दौरे के दौरान परमपावन दलाई लामा से शिष्टाचार मुलाकात की। परमपावन दलाई लामा के मैक्ल्योडगंज स्थित निवास पर हुई इस मुलाकात के बाद आडवाणी ने पत्रकारों से कहा, “हमने तिब्बत की स्थिति और चीन के रवैए के बारे में चर्चा की है।” आडवाणी ने बताया, “मैं कुछ समय पहले परमपावन दलाई लामा से मिला था और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं धर्मशाला आकर उनसे मिलूंगा और आईपीएल ने मुझे इस बात का मौका दिया।” परमपावन के सचिव छिमे छोकयप्पा ने बताया कि आडवाणी के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनकी पुत्री प्रतिभा आडवाणी भी थीं। उन्होंने परमापवन के साथ भोजन किया और यह मुलाकात करीब एक घंटा चली।